

मूक पत्रिका

निष्पक्ष, निर्भीक, स्वतंत्र आवाज...

वर्ष - 03 अंक - 02 बेमेतरा, शुक्रवार 14 अगस्त 2026 रायपुर एवं बेमेतरा से प्रकाशित कुल पेज - 08 मूल्य - 1 रूपये डाक पंजीयन- दुर्ग/1743290201/2025-27

‘आजादी की धुन’ स्वतंत्रता सेनानियों के त्याग और बलिदान को स्मरण करने का सुनहरा अवसर : मुख्यमंत्री विष्णु देव साय

- आजादी की धुन में इतिहास का गौरव, वर्तमान का कर्तव्य और भविष्य का संकल्प : मुख्यमंत्री श्री साय
- मुख्यमंत्री श्री साय संस्कृति विभाग द्वारा आयोजित ‘आजादी की धुन’ समारोह में हुए शामिल
- 100 युवा कलाकारों की एक साथ लाइव बैंड प्रस्तुति बनी आकर्षण का केंद्र, देशभक्ति के गीतों ने बांधा समां

रायपुर। राजधानी रायपुर की शाम आज देशभक्ति के सुरों से गूंज उठी। पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में संस्कृति विभाग के सहयोग से आयोजित ‘आजादी की धुन’ समारोह में प्रदेश के अलग-अलग अंचलों से आए 100 युवा कलाकारों ने विभिन्न वाद्ययंत्रों के साथ एक साथ लाइव बैंड प्रस्तुति देकर देशभक्ति का अनुपम वातावरण निर्मित किया। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय समारोह में शामिल हुए और युवा कलाकारों का उत्साहवर्धन किया। स्वतंत्रता दिवस से पूर्व आयोजित इस विशेष कार्यक्रम में देशभक्ति के गीतों की मनमोहक प्रस्तुतियों ने उपस्थित जनसमूह को राष्ट्रप्रेम के भाव से सराबोर कर दिया। मुख्यमंत्री श्री साय ने समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित ‘आजादी की धुन’ देशभक्ति की भावना को जन-जन तक पहुंचाने और स्वतंत्रता सेनानियों के त्याग,



तपस्या एवं बलिदान को स्मरण करने का सुनहरा अवसर है। आजादी की धुन’ हमें इतिहास के गौरव का स्मरण, वर्तमान के कर्तव्यों का बोध और उज्ज्वल भविष्य के निर्माण का संकल्प दिलाती है। छत्तीसगढ़ में पहली बार 100 युवा कलाकारों द्वारा एक साथ अलग-अलग वाद्ययंत्रों पर देशभक्ति की धुनों की प्रस्तुति अपने आप में अनूठा प्रयास है। उन्होंने इस अभिनव आयोजन के लिए संस्कृति विभाग और सभी कलाकारों को बधाई दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि संगीत में भावनाओं को जागृत करने और लोगों को एक सूत्र में जोड़ने की अद्भुत शक्ति होती है। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में भी गीतों, कविताओं और नारों ने देशवासियों के भीतर स्वाधीनता की चेतना जगाने में महत्वपूर्ण

भूमिका निभाई। देशभक्ति के गीतों ने कठिन परिस्थितियों में हमारे क्रांतिकारियों और सेनानियों का मनोबल बढ़ाया तथा करोड़ों भारतीयों को स्वतंत्रता के लक्ष्य के लिए एकजुट किया। आज भी जब देशभक्ति की धुनें सुनाई देती हैं, तो मन में राष्ट्र के प्रति गर्व और समर्पण का भाव स्वतः जागृत हो उठता है। मुख्यमंत्री साय ने स्वतंत्रता संग्राम के अमर सेनानियों का स्मरण करते हुए कहा कि देश की स्वतंत्रता हमें असंख्य बलिदानों के बाद प्राप्त हुई है। अनेक क्रांतिकारियों ने मातृभूमि के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए, हजारों सेनानियों ने कारावास की कठोर यातनाएं सहईं और लाखों देशवासियों ने अपना सर्वस्व राष्ट्र को समर्पित कर दिया। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, नेताजी सुभाष



चंद्र बोस, सरदार वल्लभभाई पटेल, वीर सावरकर, बाबा साहेब डॉ. भीमराव अंबेडकर सहित असंख्य राष्ट्रनायकों और स्वतंत्रता सेनानियों के संघर्ष ने स्वतंत्र भारत की नींव रखी। आज हम स्वतंत्र वातावरण में अपने सपनों को साकार कर पा रहे हैं, तो इसके पीछे हमारे पूर्वजों की तपस्या, संघर्ष और बलिदान हैं। उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता हमारे लिए केवल अधिकारों का उत्सव नहीं है, बल्कि राष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्यों और दायित्वों को निभाने का संकल्प भी है। हमें यह सदैव स्मरण रखना चाहिए कि करोड़ों देशवासियों के संघर्ष से प्राप्त इस बहुमूल्य आजादी की रक्षा करना, लोकतांत्रिक मूल्यों को मजबूत बनाना और राष्ट्र को निरंतर प्रगति के पथ पर आगे ले जाना हम सभी की साझा

जिम्मेदारी है। मुख्यमंत्री श्री साय ने स्वतंत्रता संग्राम में छत्तीसगढ़ के गौरवशाली योगदान का उल्लेख करते हुए कहा कि प्रदेश की धरती ने भी अनेक वीर सपूतों को जन्म दिया, जिन्होंने अन्याय और अंग्रेजी शासन के विरुद्ध संघर्ष किया। अमर शहीद वीर नारायण सिंह ने गरीबों और जरूरतमंदों के अधिकारों के लिए ब्रिटिश शासन को चुनौती दी और मातृभूमि के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया। बस्तर के जननायक वीर गुण्डाधुर ने भूमकाल आंदोलन का नेतृत्व कर अंग्रेजी शासन के विरुद्ध आदिवासी समाज की आवाज बुलंद की। ऐसे महान सेनानियों का शौर्य और बलिदान छत्तीसगढ़ की गौरवशाली विरासत है। मुख्यमंत्री ने कहा कि ‘आजादी की धुन’ जैसे आयोजन विशेष रूप से

युवा पीढ़ी को स्वतंत्रता के संघर्ष और उसके मूल्यों से जोड़ते हैं। नई पीढ़ी को यह जानना आवश्यक है कि जिस स्वतंत्र भारत में वे आज अपने सपनों को उड़ान दे रहे हैं, उसके पीछे कितने ही ज्ञात-अज्ञात सेनानियों का संघर्ष और त्याग है। स्वतंत्रता सेनानियों के आदर्शों से प्रेरणा लेकर राष्ट्र निर्माण में अपनी भूमिका निभाना ही उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने वर्ष 2047 में स्वतंत्रता के शताब्दी वर्ष तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प देश के सामने रख है। यह संकल्प केवल सरकार का नहीं, बल्कि 140 करोड़ देशवासियों का सामूहिक संकल्प है। इसे साकार करने के लिए समाज के प्रत्येक वर्ग, विशेषकर युवाओं को अपनी ऊर्जा, प्रतिभा और सामर्थ्य के साथ आगे आना होगा। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार भी ‘विकसित भारत’ के निर्माण में ‘विकसित छत्तीसगढ़’ के संकल्प के साथ निरंतर कार्य कर रही है। हमारा प्रयास है कि विकास की रोशनी प्रदेश के प्रत्येक गांव, प्रत्येक परिवार और प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचे तथा छत्तीसगढ़ अपनी सामर्थ्य और संभावनाओं के अनुरूप देश की प्रगति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाए। उन्होंने युवाओं से राष्ट्र प्रथम की भावना के साथ अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए विकसित भारत और विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण में योगदान देने का आह्वान किया।

राज्यसभा के मानसून सत्र की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित

सभापति ने सदन में निरंतर जारी व्यवधान पर चिंता जताई

नयी दिल्ली। राज्यसभा के मानसून सत्र की कार्यवाही गुरुवार को विपक्ष के शोर-शराबे और हंगामे के बीच खान एवं खनिज विकास संशोधन विधेयक 2026 को पारित करने के साथ अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई। इस विधेयक को हंगामे के बीच ही पूर्वाह्न शून्यकाल की जगह चर्चा और पारित करने के लिए रखा गया। चर्चा पर खान मंत्री जी किशन रेड्डी के उतर के बाद सदन में विपक्षी सदस्यों के सभी संशोधनों को ध्वनि मत से खारिज करते हुए विधेयक को पारित किया। सभापति राज्यसभा



सभापति सीपी राधाकृष्णन ने अपने संबोधन में राज्यसभा के मानसून सत्र को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित करने की घोषणा करते हुए सत्र के दौरान हुए व्यवधानों को गहरी चिंता का विषय बताया। उन्होंने कहा कि इस सत्र के दौरान लगातार अव्यवस्था बनी रही जो गहरी चिंता का विषय

है। सत्र के दौरान सदन में शोर-शराबे और हंगामे के बीच राष्ट्रीय महत्व के 12 विधेयक पारित किए गए या उन्हें पारित कर लोकसभा को लौटाया गया।

सभापति ने कहा, हमने मानसून सत्र के समय का पूरा उपयोग नहीं किया। उन्होंने कहा कि सदन की मर्यादाओं की रक्षा करना हमारी

जिम्मेदारी है क्योंकि अनुशासन और मर्यादाओं के अनुपालन से ही इस महान संस्था के प्रति लोगों का विश्वास मजबूत होता है। उन्होंने उम्मीद जताई कि आने वाले सत्र में सदस्य इसका ध्यान रखेंगे और सदन की मर्यादा रखी जाएगी ताकि देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था को और बल मिल सके। सभापति के विदाई संबोधन के बाद वंदे मातरम का गायन हुआ और कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई। गत 20 जुलाई को शुरू हुए संसद के मानसून सत्र में दोनों सदनों में विपक्ष, सत्र के प्रारंभ में दिल्ली में युवाओं के आंदोलन पर पुलिस कार्यवाही को लेकर गृह मंत्री अमित शाह के स्पष्टीकरण की मांग को लेकर हंगामा करता रहा।

चिराग पासवान से मिले बृजमोहन अग्रवाल, रखा फूड प्रोसेसिंग हब का प्रस्ताव

नई दिल्ली/रायपुर। छत्तीसगढ़ के धान को चावल तक सीमित रखने के बजाय उससे तैयार होने वाले वैल्यू-एडेड खाद्य उत्पादों को देश-विदेश के बाजार तक पहुंचाने की पहल तेज हो गई है। सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री चिराग पासवान से मुलाकात कर प्रदेश में चावल आधारित फूड प्रोसेसिंग उद्योग विकसित करने का प्रस्ताव रखा। अग्रवाल ने विशेष रूप से भाटापारा के पोहा उद्योग को आधुनिक तकनीक, बेहतर पैकेजिंग, ब्रांडिंग और मार्केटिंग से जोड़कर इसे Rice-Based Food Processing Hub के रूप में विकसित करने की संभावनाएं रखीं। उन्होंने कहा कि पोहा के साथ मुरमुरा, राइस-बेस्ड स्नैक्स, रेडी-टू-ईट उत्पाद, राइस फ्लोर



समेत कई उत्पादों की आधुनिक प्रोसेसिंग यूनिट प्रदेश में स्थापित की जा सकती है।

केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने प्रस्ताव पर सकारात्मक रुख अपनाते हुए छत्तीसगढ़ में चावल आधारित फूड प्रोसेसिंग की संभावनाओं

पर विस्तृत परियोजना तैयार कर प्रस्तुत करने को कहा। सांसद ने कहा कि प्रस्ताव में किसानों को बाजार से जोड़ने, प्रसंस्करण, पैकेजिंग, ब्रांडिंग, रोजगार और निर्यात की संभावनाओं को शामिल किया जाएगा। उनका कहना है कि धान की अधिकतम वैल्यू एडिशन प्रदेश में ही होने से किसानों, उद्यमियों और युवाओं को सीधा लाभ मिल सकता है।

गजेंद्र सिंह शेखावत से भी मिले अग्रवाल सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत से भी मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने मंत्री को छत्तीसगढ़ में आयोजित होने वाले स्वदेशी मेले में शामिल होने का निमंत्रण दिया।

चार अगस्त की घटना के बाद लिया गया फैसला एयर इंडिया मादक द्रव्यों, वर्जित दवाओं के सेवन के लिए हर पायलट की करेगी जांच

नयी दिल्ली। टाटा समूह की विमान सेवा कंपनी एयर इंडिया ने अपने हर पायलट की मादक द्रव्यों और वर्जित दवाओं के सेवन के लिए जांच करने का फैसला किया है। कंपनी ने उड़ान के बाद इस जांच को सभी पायलटों के लिए गुरुवार से अनिवार्य कर दिया है। यह फैसला गत चार अगस्त को फुकेट-दिल्ली उड़ान के दौरान विमान के हवा में अचानक 300 फुट नीचे गोता लगाने की घटना के बाद किया गया है। नशीले पदार्थ के सेवन के लिए किये गये स्क्रीनिंग टेस्ट में उड़ान का मुख्य पायलट पॉजिटिव पाया गया था। उसका सैपल प्रयोगशाला परीक्षण के लिए भेजा गया है। उड़ान संख्या एआई 2379 के साथ हुई इस गंभीर घटना में 20 यात्री और चालक दल के चार सदस्य घायल हो गये थे। उड़ान में तीन शिशुओं समेत 137 यात्री और दो पायलट समेत चालक दल के आठ



सदस्य थे। एयर इंडिया में उड़ान परिचालन के प्रमुख महेश उप्पल ने एयरलाईस के पायलटों को आज एक पत्र जारी कर बताया, ...हमने रूप के सभी पायलटों की उन सभी पदार्थों या दवाओं के लिए पूर्ण स्क्रीनिंग

कराने का निर्णय लिया है, जिनकी नियमों के तहत अनुमति नहीं है। यह परीक्षण अनिवार्य है और आज 13 अगस्त 2026 से शुरू होगा। उन्होंने बताया कि यह परीक्षण एयरलाईस की गुरुग्राम अकादमी में प्रशिक्षण के दौरान, उड़ान के बाद फ्लाइट ब्रीफिंग

सेंटर या एयर इंडिया कार्यालयों में या पायलट के संबंधित बेस द्वारा निर्धारित स्थानों पर किया जायेगा। नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) के नियमों के मुताबिक, मादक पदार्थों के लिए सभी पायलटों की जांच जरूरी नहीं है। डीजीसीए ने औचक जांच का प्रावधान किया है। उप्पल ने लिखा कि यह पहल जो नियामकीय आवश्यकताओं से आगे बढ़कर है, सुरक्षा और पेशेवर मानकों के उच्चतम स्तर को बनाए रखने तथा यात्रियों, हितधारकों और व्यापक समुदाय को आश्वस्त करने के कंपनी के दृढ़ संकल्प को दर्शाती है। उन्होंने लिखा कि दशकों से एयर इंडिया भारतीय विमानन क्षेत्र का ध्वजवाहक रहा है। इस दौरान एयरलाईस के पायलटों तथा अन्य कर्मचारियों की पेशेवर क्षमता, कोशल और सुरक्षा के प्रति प्रतिबद्धता ने लाखों यात्रियों और व्यापक समुदाय का विश्वास अर्जित किया है।

‘सेव अमेरिका एक्ट’ को मंजूरी नहीं देती है तो क्या उन्हें आपातकालीन शक्तियों का इस्तेमाल करना चाहिए। इसके जवाब में ट्रंप ने कहा, इससे भी ज्यादा असामान्य चीजें पहले हो चुकी हैं। ट्रंप ने साथ ही सीनेट से ‘सेव अमेरिका एक्ट’ पर आगे बढ़ने की अपील की। उन्होंने कहा कि मतदाताओं से नागरिकता का प्रमाण और पहचान पत्र की अपेक्षा की जानी चाहिए। ट्रंप के मुताबिक, कुछ रिपब्लिकन सीनेटर इन उपायों का विरोध कर रहे हैं, जबकि प्रतिनिधि सभा इस कानून को कई बार पारित कर चुकी है।

मेक्सिको सिटी। कोलंबिया के राष्ट्रपति अबेलादी डे ला एस्त्रिएला ने 10 अगस्त को आये शक्तिशाली भूकंप के बाद राहत और पुनर्वास कार्यों में तेजी लाने के लिए संवैधानिक आर्थिक आपातकाल घोषित किया है तथा प्रभावित क्षेत्रों के पुनर्निर्माण के लिए विशेष कोष बनाने की घोषणा की है। एस्त्रिएला ने कैराकोल टेलीविजन चैनल पर प्रसारित बयान में कहा, मैंने इस संकट से

मध्यावधि चुनाव से पहले ट्रंप का सख्त रुख, वोटर आईडी पर आपातकालीन कदम की संभावना

वॉशिंगटन। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने संकेत दिया है कि मध्यावधि चुनाव से पहले मतदाता पहचान और नागरिकता सत्यापन को अनिवार्य बनाने के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा आपातकाल घोषित करने की संभावना पर विचार किया जा सकता है। हालांकि, ट्रंप ने इस कदम की स्पष्ट घोषणा या कोई औपचारिक प्रतिबद्धता नहीं जताई है। ट्रंप ने ‘रियल अमेरिकन वॉयस’ पर वेन एलिन रूट को दिए इंटरव्यू में चुनावी प्रक्रिया की सुरक्षा को अपनी प्राथमिकताओं में बताया। उनसे पूछा गया था कि अगर सीनेट

‘सेव अमेरिका एक्ट’ को मंजूरी नहीं देती है तो क्या उन्हें आपातकालीन शक्तियों का इस्तेमाल करना चाहिए। इसके जवाब में ट्रंप ने कहा, इससे भी ज्यादा असामान्य चीजें पहले हो चुकी हैं। ट्रंप ने साथ ही सीनेट से ‘सेव अमेरिका एक्ट’ पर आगे बढ़ने की अपील की। उन्होंने कहा कि मतदाताओं से नागरिकता का प्रमाण और पहचान पत्र की अपेक्षा की जानी चाहिए। ट्रंप के मुताबिक, कुछ रिपब्लिकन सीनेटर इन उपायों का विरोध कर रहे हैं, जबकि प्रतिनिधि सभा इस कानून को कई बार पारित कर चुकी है।

उचित तरीके से निपटने के लिए संविधान में नि धा रित अ ा ि थ ि क आपातकाल लागू करने का निर्णय लिया है। नवीनतम आंकड़ों के अनुसार, भूकंप से 53,526 मकानों को नुकसान पहुंचा है और 140 इमारतें पूरी तरह ढह गयी हैं। इसके अलावा 1,819 शैक्षणिक

मध्यवधि चुनाव से पहले ट्रंप का सख्त रुख, वोटर आईडी पर आपातकालीन कदम की संभावना

‘सेव अमेरिका एक्ट’ को मंजूरी नहीं देती है तो क्या उन्हें आपातकालीन शक्तियों का इस्तेमाल करना चाहिए। इसके जवाब में ट्रंप ने कहा, इससे भी ज्यादा असामान्य चीजें पहले हो चुकी हैं। ट्रंप ने साथ ही सीनेट से ‘सेव अमेरिका एक्ट’ पर आगे बढ़ने की अपील की। उन्होंने कहा कि मतदाताओं से नागरिकता का प्रमाण और पहचान पत्र की अपेक्षा की जानी चाहिए। ट्रंप के मुताबिक, कुछ रिपब्लिकन सीनेटर इन उपायों का विरोध कर रहे हैं, जबकि प्रतिनिधि सभा इस कानून को कई बार पारित कर चुकी है।

संस्थानों, 631 सामुदायिक केंद्रों और 179 स्वास्थ्य सुविधाओं को नुकसान पहुंचा है। भूकंप में एक पैदल पुल नष्ट हो गया, जबकि 20 राजमार्ग पुलों और 203 सड़क मार्गों को नुकसान पहुंचा है। इसके अलावा 44 जलापूर्ति प्रणालियां और पांच हवाई अड्डे भी प्रभावित हुए हैं। राष्ट्रीय

झीरम का इंतजार खत्म होने को, 31 अगस्त को खुलेगा 13 साल पुराने राज का फैसला

जगदलपुर। बस्तर के इतिहास के सबसे दर्दनाक अध्यायों में शामिल झीरम घाटी नरसंहार अब न्याय के निर्णायक मोड़ पर पहुंच गया है। 25 मई 2013 को हुए इस भीषण नक्सली हमले के करीब 13 साल बाद एनआईए की विशेष अदालत ने बुधवार को अंतिम सुनवाई पूरी कर फैसला सुर्क्षित रख लिया। जगदलपुर स्थित एनआईए की विशेष अदालत के विशेष न्यायाधीश अजय सिंह राजपूत 31 अगस्त 2026 को इस बहुचर्चित मामले में अपना फैसला सुनाएंगे। सोमवार से बुधवार तक चली लगातार तीन दिनों की अंतिम बहस के दौरान अदालत में करीब 12 घंटे तक अभियोजन और बचाव पक्ष की दलीलें चलीं। सोमवार दोपहर 3 बजे अधिवक्ता दिनेश पाणिग्राही ने अंतिम बहस की शुरुआत की।

मंगलवार दोपहर 2 बजे तक उन्होंने मामले से जुड़े साक्ष्यों और तथ्यों को अदालत के समक्ष रखा। इसके बाद बचाव पक्ष के वरिष्ठ अधिवक्ता अरविंद चौधरी ने अपनी दलीलें पेश कीं। बुधवार को दोनों पक्षों की अंतिम प्रत्युत्तर दलीलें सुनने के बाद अदालत ने फैसला सुर्क्षित कर लिया। झीरम घाटी मामले की सुनवाई के दौरान कुल 101 गवाहों के बयान दर्ज किए गए। जांच एजेंसियों ने मामले में कुल 41 लोगों को आरोपी बनाया था, लेकिन इनमें से केवल 11 आरोपियों की गिरफ्तारी हो सकी। गिरफ्तार आरोपियों में से एक की इलाज/विचारण के दौरान मृत्यु हो चुकी है।

25 मई 2013: एक हमला, जिसने पूरे देश को हिला दिया 25 मई 2013 को कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा का काफिला बस्तर की झीरम

आपदा जोखिम प्रबंधन इकाई (यूपनजीआरडी) के प्रमुख डेविड तमायो ने कहा कि भूकंप के बाद राहत और बचाव कार्यों को मजबूत करने के लिए अमेरिका, इजरायल, इक्वाडोर और अल साल्वाडोर से विशेष खोज एवं बचाव दल कोलंबिया भेजे जाएंगे। तमायो ने कहा कि इन देशों से खोज एवं बचाव दलों की सहायता के लिए अनुरोध की प्रक्रिया शुरू कर दी गयी है।

घाटी से गुजर रहा था। इसी दौरान नक्सलियों ने काफिले पर घात लगाकर हमला कर दिया। हमले में तत्कालीन प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष नंदकुमार पटेल, वरिष्ठ नेता विद्याचरण शुक्ल, महेंद्र कर्मा, उदय मुदलियार समेत 29 नेताओं, कार्यकर्ताओं और सुरक्षाकर्मियों की हत्या कर दी गई। यह हमला किसी राजनीतिक दल पर हुए देश के सबसे भयावह हमलों में गिना जाता है और झीरम घाटी आज भी उस त्रासदी की गवाह बनी हुई है।

13 साल का सफर, अब फैसले की दहलीज पर हमले के दो दिन बाद 27 मई 2013 को केंद्र के निर्देश पर एनआईए ने जांच अपने हाथ में ली। इसके अगले दिन 28 मई 2013 को राज्य सरकार ने विशेष न्यायिक जांच आयोग का गठन किया। 25

सितंबर 2014 को एनआईए ने अदालत में पहली चार्जशीट पेश की। इसके बाद मामले की जांच और न्यायिक प्रक्रिया कई महत्वपूर्ण पड़ावों से गुजरी। फरवरी 2020 में राज्य सरकार ने एसआईटी का गठन किया। 6 नवंबर 2021 को न्यायिक आयोग ने जांच रिपोर्ट राज्यपाल को सौंपी और 11 नवंबर 2021 को राज्य सरकार ने दो सदस्यीय आयोग का गठन किया। वहीं 21 नवंबर 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने राज्य पुलिस की एफआईआर की जांच के खिलाफ एनआईए की याचिका खारिज कर दी। अब लंबे इंतजार के बाद वह तरीख सामने आ चुकी है, जिस पर सभी की निगाहें टिकी हैं—31 अगस्त 2026। इसी दिन एनआईए की विशेष अदालत झीरम घाटी नरसंहार से जुड़े इस लंबे न्यायिक सफर का निर्णायक अध्याय लिखेगी।

विचार-पक्ष

संपादकीय

दिल्ली में जल-भराव की समस्या से निपटने के मुद्दे पर काम कर और सियासत ज्यादा होती है। हमेशा की तरह इस दफा भी यही देखने-सुनने को मिल रहा है। राष्ट्रीय राजधानी होने के नाते यह उम्मीद की जाती है कि दिल्ली में अन्य शहरों के मुकाबले हर मोर्चे पर व्यवस्था बेहतर होगी। मगर इसे विडंबना ही कहा जाएगा कि यहां बरसात से जुड़ी समस्याएँ वर्षों से जस की तस बनी हुई हैं। गर्मी के मौसम में यहां कई इलाकों में लोग

पानी की बूंद-बूंद के लिए तरस जाते हैं, तो बरसात में पानी घरों और सड़कों को ही डुबो देता है। दिल्ली में सत्ता भले ही बदलती रहती है, लेकिन व्यवस्था में कोई बदलाव या सुधार नजर नहीं आता है। यहां नई सरकार के कमान संभालने के बाद दावे किए जा रहे थे कि शहर को जल-भरवा मुक्त बनाने का सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाएगी, लेकिन बीतेतीनों दशकों में दिल्ली में बारिश ने सरकार के इन दावों पर ही पानी फेर दिया है। भारतीय

मौसम विभाग के मुताबिक, वर्ष 2011 के बाद अमृत के पहले समाह में शुक्रवार को यहां सबसे अधिक 127 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। जाहिर है कि जब एक घंटे की तेज बारिश में ही दिल्ली पानी-पानी हो जाती है, तो दिन भर की बरसात में क्या हाल होगा, इसके दृश्य इन दिनों कई जगह देखने को मिल रहे हैं। राष्ट्रीय राजधानी में भारी बारिश से एक बार फिर जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया। कई प्रमुख सड़कें तालाब बन गईं,

जिससे वाहनों की रफ्तार थम गई। महारौली-बदरपुर रोड से लेकर महिलानपुर, आइट्टीओ, शकरपुर और छतरपुर तक की सड़कों पानी में डूब गई। खानपुर से ओखला मोड़ के बीच कई किलोमीटर तक गाड़ियां रेंगती नजर आईं। इस दौरान यात्री घंटों जाम में फंसे रहे। इसके अलावा कई इलाकों में घरों में पानी भर जाने से लोगों को परेशानियां झेलनी पड़ीं। ऐसे में यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि सरकार की ओर से जो दावे किए जा रहे

थे, उनका आधार क्या था? अगर जल-प्रायश की समस्या को खत्म करने के लिए प्रभाव किए गए, तो उनका नतीजा जमीन पर क्यों नहीं दिख रहा है? आखिर क्या वजह है कि बारिश के पानी की निकासी से जुड़ी योजनाओं पर करोड़ों रुपये खर्च करने के बाद भी स्थिति में सुधार नहीं हो पा रहा है? गौरतलब है कि सरकार की ओर से हर साल बरसात शुरू होने से पहले सीवेज की नालियों और बड़े नालों की सफाई का जोर-

शोर से अभियान शुरू किया जाता है। सवाल है कि क्या यह अभियान सिर्फ कागजों तक ही सीमित रहता है? इसे कारगर तरीके से धरातल पर उतारने की जिम्मेदारी आखिर किसकी है? शहर में बारिश के पानी की निकासी के माफ़ूल बंदेबस्त क्यों नहीं हो पा रहे हैं? इसका एक कारण यह भी है कि दिल्ली में जल-भराव की समस्या से निपटने के मुद्दे पर काम कम और सियासत ज्यादा होती है।

गजब है रुस से भारत तक ट्रेन चलाने का प्रस्ताव, मोदी-पुतीन की रणनीति के कायल हो जाएंगे

(नीरज कुमार दुबे)

देखा जाये तो यह प्रस्ताव केवल रेतने लाइन बिछाने की सामान्य योजना नहीं है। इसके पीछे बदलती वैश्विक भू-राजनीति, उर्जा सुरक्षा, व्यापार मार्गों की विश्वसनीयता और रूस-भारत के बीच लंबे समय से चली आ रही रणनीतिक दोस्ती का बड़ा आयाम छिपा है। पश्चिम एशिया में जरी अस्थिरता और समुद्री व्यापार मार्गों पर बढ़ते जोरिफम के बीच रूस ने भारत के साथ अपनी रणनीतिक सहस्रदोस्ती को एक नई दिशा देने वाला बड़ा प्रस्ताव सामने रखा है। रूस के उप प्रधानमंत्री मरात खुसगुलिन ने मॉस्को से हिंद महासागर तक सीधे रेल संपर्क की संभावनाएं तलाशने की बात कही है। उन्होंने कहा है कि बोसफोरस और होमुज जलमलमरूमध्य जैसे रणनीतिक समुद्री मार्गों पर बढ़ते जोरिफम को देखते हुए रूस और भारत के बीच वैकल्पिक जमीनी संपर्क विकसित करना जरूरी हो गया है। रूसी समाचार एजेंसी के हवाले से खुसगुलिन ने कहा कि तुर्कमेनिस्तान, ईरान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के रास्ते भारत तक पहुंचने वाले विकल्पों पर विचार किया जा सकता है। और भारत तक पहुंचने उपलब्ध कराने वाला कोई भी विकल्प स्वीकार्य होगा। देखा जाये तो यह प्रस्ताव केवल रेतने लाइन बिछाने की सामान्य योजना नहीं है। इसके पीछे बदलती वैश्विक भू-राजनीति, उर्जा सुरक्षा, व्यापार मार्गों की विश्वसनीयता और रूस-भारत के बीच लंबे समय से चली आ रही रणनीतिक दोस्ती का बड़ा आयाम छिपा है। खास तौर पर ऐसे समय में जब पश्चिम एशिया के संघर्ष ने दुनिया को यह दिखा दिया है कि किसी एक समुद्री चोकपॉइंट पर अत्यधिक निर्भरता वैश्विक व्यापार के लिए कितनी बड़ी कमजोरी बन सकती है।

होमजुज संकट ने बढ़ाई वैकल्पिक रास्ते की जरूरत -
रूस के इस प्रस्ताव को समझने के लिए मौजूदा अमेरिकनीतिक परिस्थितियों को देखना जरूरी है। 28 फरवरी को भूमिका और इजरायल की ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई के बाद पश्चिम एशिया में तनाव तेजी से बढ़ा। ईरान की जबाली मिसाइल और ड्रोन कार्रवाई के बाद फारस की खाड़ी और होमजुज जलडमरूमध्य में समुद्री यातायात पर गंभीर असर पड़ा। रिपोर्टों के मुताबिक होमजुज से होकर गुजरने वाला वैश्विक तेल व्यापार का करीब पांचवां हिस्सा प्रभावित हुआ। हम आपको बता दें कि होमजुज जलडमरूमध्य फारस की खाड़ी को आमोन की खाड़ी से जोड़ता है और यह दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण ऊर्जा मार्गों में शामिल है। इसी तरह तुर्किये के नियंत्रण वाला बोस्फोरस जलडमरूमध्य काला सागर को मरमारा सागर से जोड़ता है। ऐसे समुद्री 'चोकपॉइंट' किसी भी संकट की स्थिति में अंतरराष्ट्रीय व्यापार के लिए गंभीर जोखिम पैदा कर सकते हैं। यही वजह है कि मार्को एबल समुद्री मार्गों के साथ-साथ वैकल्पिक स्थलीय व्यापार नेटवर्क विकसित करने पर जोर दे रहा है।

भारत इस योजना के केंद्र में क्यों? - इस प्रस्ताव का सबसे महत्वपूर्ण पहलु यह है कि रूस ने संभावित रेल मार्ग के अंतिम गंतव्य के रूप में भारत को विशेष महत्व दिया है। यह संयोग नहीं है। भारत और रूस पहले से ही इंटरनेशनल नाव सांख्यिकी (आईएनएसआईटी) के प्रमुख साझेदारों में हैं। रूस को ईरान और भारत से जोड़ने की महत्वाकांक्षी परियोजना है। इसमें रेल, सड़क और समुद्री परिवहन का संयोजन शामिल है। मौजूदा व्यवस्था में रूस से आने वाला माल काजखस्तान और तुर्कमेनिस्तान होते हुए ईरान पहुंच सकता है। वहां से रेल के ज़रिए बंदर अब्बास जैसे बंदरगाहों तक और फिर काजखस्तान-तुर्कमेनिस्तान-ईरान मार्ग की भूमिका महत्वपूर्ण है। इस लिहाज से रूसी उप प्रधानमंत्री खुसनुलिन का प्रस्ताव बिल्कुल शून्य से शुरू होने वाली परियोजना नहीं, बल्कि मौजूदा कनेक्टिविटी ढांचे को और आगे बढ़ाने की सोच है। लक्ष्य यह

है सकता है कि आने वाले समय में रूस और भारत के बीच माल दुलाई को ज्यादा तेज, भरोसेमंद और बहुविधतापूर्ण बनाया जाए। अभी 'माँस्को से भारत' सीधी ट्रेन नहीं हलाकि इस खबर को यात्रियों और रेलवे प्रेमियों की कल्पना को जरूर हवा दी है लेकिन पिछलेहल इसे माँस्को से दिल्ली या मुंबई तक चलने वाले सीधी यात्री ट्रेन समझना जल्दबाजी होगी। अभी तक रूस या भारत की ओर से इस तरह की यात्री सेवा या पर्यटन केन्द्रित ट्रेन की कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। रूसी उप प्रधानमंत्री वे प्रस्ताव का मूल उद्देश्य फ्रेट, लॉजिस्टिक्स और रणनीतिक कनेक्टिविटी है। वैसे भी यात्री सेवा शुरू करने में अलग-अलग व्यवहारिक अड़चनें होंगी जैसे की देशों के वीजा, अलग-अलग रेल गैज, सीमा और सुरक्षा जांच, विभिन्न देशों के रेलवे के बीच समय-सारणी का तालमेल तथा यात्री सुविधाओं का अभाव लेकिन भविष्य की संभावना को पूरी तरह खारिज भी नहीं किया जा सकता। यदि कॉरिडोर स्थिर, सुरक्षित और आर्थिक रूप से व्यवहार्य बनता है तो बाद में यात्री रेल सेवा की संभावना तलाशना संभव होगा। ऐसी ट्रेन यूरेशिया के विशाल भूभाग, मध्य एशिया और ऐतिहासिक सिल्क रूट के शहरों को जोड़ने वाला असाधारण यात्रा बन सकती है। भारत के लिए बड़ा रणनीतिक लाभ वैसे रूस के इस प्रस्ताव का सबसे बड़ा फायदा भारत की कनेक्टिविटी की रणनीतिक विविधता के रूप में मिल सकता है। भारत की विदेश और आर्थिक नीति लंबे समय से यह सुनिश्चित करने की कोशिश कर रही है कि उसकी व्यापारिक आपूर्ति किस एक मार्ग या एक देश पर निर्भर न रहे। इसलिए रूस से भारत तक मजबूत स्थलीय नेटवर्क बनने पर भारतीय कारोबारियों की सीधा बाजार तक पहुंच का एक वैकल्पिक रास्ता मिलेगा। इससे रूसी, उर्जा संसाधन, उर्वरक, धातु, कृषि उत्पाद और अन्य वस्तुओं की आवाजाही अधिक लचीली हो सकती है। दूसरा बड़ा लाभ समय और लागत का हो सकता है। आईएनएसटीडी की मूल उद्देश्य भी पारंपरिक समुद्री मार्गों की तुलना में माल परिवहन को तेज और अधिक प्रतियोगी बनाना है। पूर्ण रूप से विकसित नेटवर्क भारत-रूस व्यापार को नई गति दे सकता है। एक ओर सबसे महत्वपूर्ण लाभ उर्जा सुरक्षा है। होमरुज जैसी किसी एक संवेदनशील समुद्री पट्टी पर निर्भरता कम होने से भारत वैश्विक संकटों के दौरान अपनी आपूर्ति श्रृंखला को ज्यादा प्रभावी ढंग से संभाल सकता है।

पाकिस्तान वाला रास्ता सबसे कठिन कड़ी - हालांकि प्रस्तावित मार्ग में पाकिस्तान का नाम आना इसे रणनीतिक रूप से बेहद दिलचस्प और चुनौतीपूर्ण बनाता है। रूस ने संभावित

विकल्पों में तुर्कमेनिस्तान, ईरान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान का उद्देश्य किया है। लेकिन भारत-पाकिस्तान संबंधों की मौजूदा जटिलताओं को देखते हुए इस रास्ते को तत्काल व्यवहार्य मानना कठिन होगा। यही कारण है कि भारत के लिए ईरान और मध्य एशिया के रास्ते विकसित होने वाले वैकल्पिक नेटवर्क अधिभू व्यावहारिक महत्व रखते हैं।

चीन के लिए भी बदलता समीकरण - इस परियोजना की एक व्यापक भू-राजनीतिक प्रभाव चीन पर भी पड़ सकता है। चीन वर्षों से ब्रेट एण्ड रोड इन्वेस्टिट के जरिए यूरोशिया में अपना प्रभुत्व बढ़ा रहा है। इसमें मुकाबले भारत-रूस समर्थित आईनस्पटसी और उससे जुड़े नए रेल नेटवर्क यूरोशिया में एक वैकल्पिक आर्थिक गलियारा मजबूत कर सकते हैं। भारत को इसमें यह अवसर मिलेगा कि वह चीन केंद्रित कनेक्टिविटी मॉडल के समानांतर अपना प्रभाव क्षेत्र विकसित करे। मध्य एशिया, ईरान और रूस के साथ भारत के आर्थिक संबंधों को भी इसमें मजबूती मिल सकती है। रूस-भारत की दोस्ती का भी आर्थिक अन्वय सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह प्रस्ताव भारत और रूस के रशों को केवल रक्षा और ऊर्जा मध्येग तक सीमित नहीं रखता, बल्कि उन्हें कनेक्टिविटी और व्यापार की नई धुरी बन ले जाता है। रूस के लिए भारत हिंद महासागर तक पहुंच का महत्वपूर्ण द्वार है, जबकि भारत के लिए रूस यूरोशिया के विशाल बाजार तक पहुंच का प्रमुख साधक है। इसलिए दोनों देशों के बीच इस परियोजना में स्वाभाविक रूप से एक-दूसरे से जुड़ने हैं। इसमें जाये तो बदलती दुनिया में समुद्री रास्तों पर जोखिम बढ़ रहे हैं और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाएं लगातार नए झटकों का सामना कर रही हैं। ऐसे में रूस का मॉस्को से हिंद महासागर तक रेल संपर्क को विचार भले ही औसी शुरुआती चरण में हो, लेकिन इसकी रणनीतिक दिशा बेहद स्पष्ट है। यानी व्यापार के लिए सिर्फ एक रास्ते पर निर्भर मत रहिए, विकल्पों का ऐसा नेटवर्क तैयार कीजिए जिसे संकट भी आसानी से बाधित न कर सके। बहाने हल, भारत के लिए यह सिर्फ रूस तक पहुंचने वाली रेल लाइन नहीं होगी। यह यूरोशिया से हिंद महासागर तक भारत की रणनीतिक पहुंच को ऊर्जा सुरक्षा, व्यापारिक स्वायत्तता और वैश्विक कनेक्टिविटी का मजबूत करने वाला संभावित नया गलियारा बन सकती है। और भारत-भारत-रूस की पुरानी मित्रता इस परियोजना को राजनीतिक इच्छाशक्ति और आर्थिक निवेश का आधार देती है, तो आने वाले वर्षों में यह कॉरिडोर एशिया की बदलती भू-आर्थिक तस्वीर का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन सकता है। (इस लेख में लेखक के अपना विचार हैं।)

क्या 'इस्लामिक नाटो' से भारत को कूटनीतिक चुनौतियां बढ़ेंगी? अमेरिका व चीन की कोई परीक्षा चाल तो नहीं?

(कमलेश पांडे)

पाकिस्तान को नया रणनीतिक
ऑक्सीजन मिल सकता है- पाकिस्तान
के पास परमाणु क्षमता, तुर्किये के पास
मजबूत रक्षा उद्योग/सैन्य क्षमता और
सऊदी अरब के पास वित्तीय व ऊर्जा
शक्ति है। इन तीनों का संयोजन
पाकिस्तान को भारत के मुकाबले
कूटनीतिक और सैन्य दबाव बनाने के
नए साधन दे सकता है। एशिया में ईरान
और रूस के दांवपेंच से निपटने के
लिए या फिर अमेरिका और चीन की
शह पर पहले पाकिस्तान और सऊदी
अरब के बीच और अब तुर्किये के
साथ भी मका में जो रक्षा समझौते हुए
हैं, उसके दृष्टिगत भारतवासियों के
दिलोदिमाग में बस एक ही सवाल कौंध
रहा है कि क्या कथित 'इस्लामिक
नाटो' से भारत की कूटनीतिक
चुनौतियां बढ़ेंगी? क्या इससे निपटने में
रूस-ईरान से रक्षा सम्बन्धों को और
मजबूती दी जानी चाहिए? या फिर
अमेरिका या चीन या फिर दोनों के
इशारे पर हुए इस गर्वजन्य के पीछे कोई
प्रोक्ष चाल तो नहीं है? तो जवाब होगा
कि हाँ-भारत की कूटनीतिक चुनौतियां
बढ़ सकती हैं, लेकिन इसे अभी सोच
सकते हैं 'इस्लामिक नाटो' कहना
जल्दबाजी होगी। दरअसल, गत 7
अगस्त 2026 को मका में सऊदी
अरब, तुर्किये और पाकिस्तान ने एक
संयुक्त रक्षा समझौता किया है, जिसमें
एक पर सशस्त्र हमला तीनों पर हमला
माना जाएगा। यह पहले के सऊदी-
पाकिस्तान रक्षा समझौते का विस्तार है।
लिहाजा भारत के लिए असली चिंता
यह है कि- पहली, पाकिस्तान को नया
रणनीतिक ऑक्सीजन मिल सकता है-
पाकिस्तान के पास परमाणु क्षमता,
तुर्किये के पास मजबूत रक्षा
उद्योग/सैन्य क्षमता और सऊदी अरब
के पास वित्तीय व ऊर्जा शक्ति है। इन
तीनों का संयोजन पाकिस्तान को भारत
के मुकाबले कूटनीतिक और सैन्य
दबाव बनाने के नए साधन दे सकता
है। दूसरा, तुर्किये का शामिल होना
विशेष रूप से महत्वपूर्ण है- भारत-
पाकिस्तान तनाव के दौरान तुर्किये ने
कई बार इस्लामाबाद के पक्ष में
राजनीतिक रुख अपनाया है। अब यदि
वह किंसी औपचारिक समूहिक रक्षा
व्यवस्था का हिस्सा है, तो भविष्य के
भारत-पाकिस्तान संकट में उसका
वजन और बढ़ सकता है। तीसरा,
सऊदी अरब को पाकिस्तान का स्थायी
सैन्य सहयोगी मान लेना भी गत
होगा- रियाद के भारत के साथ बड़े
आर्थिक, ऊर्जा और रणनीतिक हित हैं।
इसलिए सऊदी नेतृत्व के लिए
पाकिस्तान के साथ रक्षा सहयोग और
भारत के साथ रणनीतिक संबंध-दोनों

को साथ लेकर चलना संभवतः अधिव्यवहार
उपयोगी है।

क्या इसके पीछे रूस विरोध ? अमेरिका की चाल हो सकती है ? - जवाब- संभावना अभी हो सका नहीं जा सकता, लेकिन अभी इसका प्रमाण नहीं है। दिलचस्प बात यह है कि जनवरी 2026 में ही रणनीतिक विश्लेषण में यह कहा जा रहा था कि तुर्किये इस तरह के गठबंधन का इस्तेमाल नाटो के भीतरी अपनी बार्गिंग पावर बढ़ाने और हेडजिंग के लिए कर सकता है। चूंकि अमेरिकन के लिए ऐसा ढांचा कुछ परिस्थितियों में उपयोगी भी हो सकता है, क्योंकि ईरान के विरुद्ध क्षेत्रीय डिड्रेशन बढ़ाना पश्चिम एशिया में अमेरिकी सैन्य बोझ कम करना, सऊदी सुरक्षा को वैकल्पिक रूप से मजबूत करना, तुर्किकी को पश्चिमी सुरक्षा ढांचे से पूरी तरह दूर जाने से रोकना और पाकिस्तान को चीन के पूर्ण प्रभाव में जाने से रोकना उसका असली मकसद है। इसलिए इस तरह अमेरिका के खिलाफ गठबंधन मानिष्ठ उतना ही गलत होगा जितना इसे निश्चित रूप से अमेरिकी परियोजना मान लेना। सुलतान सवाल- और जहाँ तक चीन का जवाब है? यहाँ मामला और दिलचस्प है। जवाब- चीन के पाकिस्तान के साथ अत्यंत गहरे रक्षा संबंध हैं और सऊदई अरब के साथ उसके आर्थिक संबंध लगातार बढ़ते हैं। यदि यह त्रिकोण अरब-चीन-अमेरिका के बीच के बीच चक्कर विस्तृत हो जाये, तो बीजिंग को पश्चिम एशियाई पाकिस्तान हिंद महासागर के बीच अपना प्रभाव बढ़ाने का अवसर मिल सकता है। लेकिन चीन के लिए भी समस्या है- सऊदी अरब अमेरिका से पूरी तरह अलग नहीं होना चाहता और तुर्किये नाटो का सदस्य है। इसलिए अभी चीन-नेतृत्व वाला गठबंधन कहेना वास्तविकता से आगे निकलना होगा।

आखिर भारत को किस बात से सबसे ज्यादा सावधान रहना चाहिए? - मेरे आकलन में 'इस्लामी नाटो' शब्द से ज्यादा महत्वपूर्ण इसमें संभावित नेटवर्क प्रभाव हैं। यदि भविष्य में इसमें कतर, अज़रबैजान, मिस्र यथ अन्य मुस्लिम-बहुल देश किसी रूप में जुड़ते हैं, तो तत्काल बिना कसौटी है। मध्य में पाकिस्तान की ओर से तुर्किये और कतर के संभावित जुड़ाव की बात भी सामने आई थी। तब भारत को तीनों मोर्चों पर चुनौती मिल सकती है- पश्चिम एशिया पाकिस्तान ? तुर्किये, यानि पाकिस्तान को पहली बार भारत के विरुद्ध केवल द्विपक्षीय नहीं बल्कि बहु-देशीय कूटनीतिक समर्थन तब बनाने का अवसर मिल सकता है।

लेकिन भारत की स्थिति भी कमजोर नहीं है, क्योंकि भारत को प्रतिक्रिया में किसी एंटी इस्लामिक ब्लाक में जाने का जरूरत नहीं है।

पराया धन नहीं, परिवार का आधार- बेटियों को लेकर कैसे बदल रही है भारत की सोच?

(रचना सिद्धा)

नागौर में बेटी का 'पाग दस्तूर' और कारा रिपोर्ट में गोद लेने की 8व बढोतरी बदलती सामाजिक सोच का प्रमाण है। बेटीयाँ अब बोझ नहीं, हर क्षेत्र में सफलता और बुद्धि के सहारा बनकर देश का मान बढा रही हैं। कुछ समय पहले राजस्थान के नागौर जिले के सुरियास गांव में पहली बार एक बेटी का 'पाग दस्तूर' किया गया। राजस्थान की पारंपरिक सामाजिक व्यवस्था में पिता के निधन के बाद परिवार के बड़े बेटे को परिवार का उत्तराधिकारी घोषित किया जाता है। इसी को 'पाग दस्तूर' कहते हैं। अगर परिवार में पुत्र नहीं होता, तो कई परिवार दत्तक पुत्र लेकर यह रस्म निभाते हैं। पंद्रह जुलाई को सुरियास गांव के कान सिंह राठौड़ का बीमारी से निधन हो गया। उनके परिवार में एकमात्र संतान उनकी दस वर्षीय बेटी है। बारहवें की रस्म के बाद किसी निकट संबंधी को दत्तक लेकर 'पाग दस्तूर' कराने की चर्चा चल रही थी। मगर कान सिंह की माता और पत्नी ने साफ शब्दों में कहा कि क्योंकि उनका एकमात्र संतान पुत्री है, इसलिए उसका ही 'पाग दस्तूर' किया जाएगा।

इस बदलाव से परिवार ने पुरानी परंपरा को नया स्वरूप देते हुए मजबूत संदेश दिया है कि परिवार की पहचान और सम्मान केवल देते से नहीं, बल्कि बेटी से भी आगे बढ़ सकता है। गांव के लोगों का भी कहना है कि इस निर्णय ने वर्षों की सामाजिक सोच में बदलाव ला दिया है जो बेटीयों को बराबरी का अधिकार और सम्मान देने का संदेश देता है। पिछले कुछ वर्षों में लड़कियों को गोद लेने का चलन बढ़ा है।

इस बात की पुष्टि करती हाल ही में जारी 'सेंट्रल अडाप्टेशन रिसोर्स अथारिटी' की एक रिपोर्ट के मुताबिक पिछले वर्ष के मुकाबले वर्ष 2025-26

आज बेटियां किसी भी क्षेत्र में पुरुषों से पीछे नहीं हैं। खेल के मैदान से लेकर अंतरिक्ष तक, कारपोरेट के बोर्डरूम से लेकर सीमा की सुरक्षा तक हर जगह बेटियों ने अपनी काबिलियत का लोहा मनवाया है। ओलंपिक पदकों से लेकर सिविल सेवाओं तक, जब माता-पिता हर जगह बेटियों का परचम लहराते देखते हैं, तो उनका गर्व से सिर ऊंचा हो जाता है। यह सफलता इस बात का प्रमाण है कि अवसर मिले, तो बेटियां आसमान छू सकती हैं। उन्होंने यह सिद्ध कर दिया है कि अवसर मिलने पर वे किसी भी क्षेत्र में लड़कों से कम नहीं हैं।

में लड़कियों को गोद लेने वालों की संख्या में आठ फीसद की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। वह समय बीत गया, जब बेटियों को बोझ माना जाता था और बेटों को परिवार का सम्मान।

तब बेटियाँ परया धन मानी जाती थी और बेटे को वंश को आगे बढ़ाने वाला और बुढ़ापे का सहारा बनने वाला कहा जाता था। यहां तक कि अंतिम संस्कार बेटों के हाथों से होने पर मुक्ति मिलने की सोच हमारी मानसिकता पर हावी थी। इसी मानसिकता के प्रभाव में हमने सदियों तक लड़कियों को दोयम दर्जे का नागरिक बना कर रखा।

सादियों से भारतीय समाज में पुत्र माह एक कड़वी सच्चाई बन कर हमारे साथ रहा है। मगर अरा हवा का रुख बदल रहा है। आधुनिक भारत में यह एक नया और सुखद बदलाव दिखाई दे रहा है। न केवल भारत में, बल्कि दुनिया भर में समाज की सोच में तेजी से बदलाव आ रहा है। पहले जहाँ बेटों को प्राथमिकता दी जाती थी वहीं अब बेटियों के प्रति झुकाव बढ़ रहा है।

एक विश्लेषण के मुताबिक 1980 से अब तक करीब पांच करोड़ बेटियां जन्म से पहले ही खत्म कर दी गईं। यह आंकड़ा अब तेजी से घट रहा है। विश्लेषण के मुताबिक 2001 से अब तक 70 लाख बेटियां

बचाई गई हैं। चीन, भारत और दक्षिण कोरिया जैसे देशों में लिंगानुपात तेजी से सामान्य होता जा रहा है। माता पिता अब बेटियों को ज्यादा समझदार, संवेदनशील और कम चुनौतीपूर्ण मानने लगे हैं।

कई देशों में अब यह धारणा भी जोर पकड़ती जा रही है कि बेटीयाँ बुजुर्ग माता-पिता की बेहतर देखभाल करती हैं। यह सोच भारत में भी तेजी से बढ़ रही है और शायद यही कारण है कि अब एक संतान बेटी हो जाने के बाद भी दंपति लड़कें के लिए दूसरी संतान के बारे में नहीं सोचते। यह समाज की सोच में आया एक सकारात्मक बदलाव नहीं, बल्कि सोच की उस स्कीर्णता पर भी कारगर चोट है जिसने लंबे समय तक बेटीयों को 'परया धन' मान कर हाशिये पर रखा। इस सकारात्मक बदलाव के पीछे कई अहम कारन हैं, जिसने लोगों की मानसिकता को बदलने में बड़ी भूमिका निभाई है।

आज बेटियाँ किसी भी क्षेत्र में पुरुषों से पीछे नहीं हैं। खेल के मैदान से लेकर अंतरिक्ष तक, कारपोरेट के बोर्डरूम से लेकर सीमा की सुरक्षा तक हर जगह बेटियों ने अपनी कार्रवाइयत का लोहा नवाया है। ओलंपिक पदकों से लेकर स्मिथल सेनाओं तक, जब माता-पिता हर जगह बेटियों का परचम लहराते देखते हैं, तो उनका गर्व से सिर उंचा हो जाता है।

यह सफलता इस बात का प्रमाण है कि अवसर मिलते, तो बेटियाँ आसमान छू सकती हैं। उन्होंने अपने सिद्ध कर दिया है कि अवसर मिलने पर पवे किसी भी क्षेत्र में लड़कों से कम नहीं हैं। उनकी सफलता ने समाज की पुरानी धारणाओं को तोड़ते हुए बेटियों के प्रति सम्मान और भरोसे को मजबूत किया है।

अवसर देखा जाता है कि बेटियों शादी के बाद भी अपने माता-पिता के प्रति उतनी ही संवेदनशील और जिम्मेदार रहती हैं, जितना कि शादी से पहले थीं।

बुद्धिमान में माता-पिता की देखभाल करने और उनका भगवानकर्म सहारा बनने में बेटियाँ किसी से कम साबित नहीं हो रही हैं। समाज में अब यह बात गहराई से महसूस की जाने लगी है कि बेटा केवल एक कुरल का नाम आगे बढ़ता है, लेकिन बेटी दो-दो परिवारों को रोशन करती है।

प्रायः दूर में वृद्धि और कानून के प्रति बढ़ती जागरूकता ने भी इस बदलाव की नींव रखी है। 'बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ' जैसे सरकारी अभियानों, कन्या भ्रूण हत्या के खिलाफ सख्त कानून और संपत्ति में बेटियों के समान अधिकारों जैसे विधायी कदमों ने लोगों को यह सोचने पर मजबूर किया है कि बेटा और बेटी दोनों बराबर हैं।

केंद्र और राज्य सरकारों की विभिन्न योजनाओं ने भी इस

बदलाव में अहम भूमिका निभाई है। 'बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ' जैसे अभियान ने कन्या भ्रूण हत्या रोकने, बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने और समाज में सकारात्मक सोच विकसित करने का कार्य किया है। कई राज्यों में कन्या जन्म पर आर्थिक सहायता, छात्रवृत्ति, निशुल्क शिक्षा तथा उच्च शिक्षा के लिए विशेष प्रोत्साहन जैसी योजनाओं ने परिवारों को बेटीयों के भविष्य के प्रति आश्वस्त किया है।

आजकल के छोटे या एकल परिवारों में माता-पिता लिंग भेद से परे जाकर केवल एक या दो बच्चों की पवरशिर पर ध्यान दे रहे हैं। अब लोग लिंग सबा से पूरी तरह बेफिक्र हैं कि उनका इकलौता बच्चा बेटी या बेटी। वे बेटी की पवरशिर भी उसी लाड़-प्यार, शिक्षा और संसाधनों के साथ कर रहे हैं जो कभी सिर्फ बेटों का हक समझा जाता था।

स यात्रा को पूरा होने में अभी कुछ वक्त लगेगा। न केवल शहरी बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी बेटियों को लेकर जो स्वीकार्यता और ललक बढ़ी है, वह उम्मीद जगाने वाली है। हालाँकि देश के दूरदराज इलाकों में आज भी कुछ कुरीतियाँ और भेदभाव के अंश बाकी हैं।

मृदु क्षेत्रों में अब भी लैंगिक भेदभाव, बाल विवाह और शिक्षा से वंचित कर दिए जाने जैसी समस्याएँ मौजूद हैं। बदलाव के लिए जो हमारी गति है, उससे मंजिल बहुत दूर नहीं लगती। जब समाज बेटीयों को बोझ नहीं, बल्कि एक वरदान के रूप में देखने लगता है, तब केवल एक परिवार और समाज का नहीं, बल्कि पूरे राष्ट्र का उत्थान होता है। इसलिए बेटीयों को सही शिक्षा वातावरण, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और आत्मनिर्भर बनने के अवसर प्रदान करना हम सभी का जिम्मेदारी है। बेटीयों की बढ़ती चाह एक समृद्ध, समतावादी और संवेदनशील भारत के निर्माण का सबसे सशक्त प्रतीक है।

राष्ट्रगान के साथ गरिमामय समापन—यात्रा के ऐतिहासिक और भव्य समापन पर विधायक अनुज शर्मा ने रैली में शामिल सभी देशभक्त कार्यकर्ताओं, मातृशक्ति, युवाओं और क्षेत्र के सम्मानित नागरिकों का हृदय से आभार व्यक्त किया। इसके पश्चात्, पूरे रैली का समापन राष्ट्रगान के समूहिक और गरिमामय गायन के साथ हुआ जिससे पूरा माहौल राष्ट्रभक्ति के रंग में सराबोर हो गया।

कुसमी में निकली इस विशाल तिरंगा यात्रा ने स्वतंत्रता दिवस से पहले नगर में राष्ट्रप्रेम और एकता का ऐसा संदेश दिया, जिसने बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक सभी को देशभक्ति के रंग में रंग दिया। तिरंगे की शान में उमड़ा जनसैलाब पूरे आयोजन का प्रमुख आकर्षण रहा।

गैलेक्सी Z फोल्ड8 सीरीज़: फोल्डेबल तकनीक में एक बड़ी छलांग

गुरुग्राम: सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स ने पिछले महीने 22 जुलाई को अपनी गैलेक्सी Z सीरीज़ की 8वाँ पीढ़ी के स्मार्टफोन्स पेश किए, जिनमें गैलेक्सी Z फोल्ड8 अल्ट्रा, गैलेक्सी Z फोल्ड8, और गैलेक्सी Z फिलप8 शामिल हैं। पिछले कई सालों में यूज़र्स से मिले फीडबैक और इंजीनियरिंग में किए गए नवाचारों के आधार पर तैयार किए गए ये स्मार्टफोन फोल्डेबल तकनीक में एक महत्वपूर्ण छलांग हैं, जो बाज़ार में सबसे बेहतरीन फोल्डेबल के रूप में अपनी स्थिति की और मजबूत करते हैं।

इन डिवाइसेस के सफल लॉन्च के बाद, Sunghoon Moon, Executive Vice President and Senior E&xecutive of Mobile R&D Office – Hardware, Mobile eXperience (MX) Business at Samsung Electronics ने इंजीनियरिंग को लेकर कंपनी के यूज़र-केंद्रित दृष्टिकोण के बारे में अपनी राय व्यक्त की।

उन्होंने कहा, शुरुआत से ही, हमने फोल्डेबल डिवाइसेस को एक ऐसे अवसर के रूप में देखा, जिससे लोगों के स्मार्टफोन इस्तेमाल करने के तरीके को नया रूप दिया जा सके। सात पीढ़ियों के सफर में, हमने यह समझा है कि लोग अपने डिवाइसेस को कैसे खोलते हैं, साथ रखते हैं, अनफोल्ड करते हैं और उन पर भरोसा करते हैं।

यूज़र्स से मिली इन जानकारीयों ने सैमसंग की इंजीनियरिंग प्राथमिकताओं को आकार दिया : बड़ा और अधिक इमर्सिव डिस्प्ले, ड्यूरेबिलिटी से समझौता किए बिना पतली और हल्की डिज़ाइन, अल्ट्रा-परफॉर्मेंस, जो फोल्डेबल फॉर्म फैक्टर के अटूटे फायदों को बरकरार रखती है।

सैमसंग ने पुणे में FläktGroup की नई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के साथ AI डेटा सेंटर कूलिंग क्षेत्र में अपनी स्थिति मजबूत की

सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स ने आज घोषणा की कि महाराष्ट्र के पुणे में FläktGroup (एक सैमसंग कंपनी) द्वारा संचालित नई हीटिंग, वेंटिलेशन और एयर कंडीशनिंग (HVAC) मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का काम पूरा हो गया है। इससे भारत और एशिया-पैसिफिक में तेजी से बढ़ रहे,बु डेटा सेंटर कूलिंग और HVAC मार्केट में सैमसंग की स्थिति और मजबूत होगी।

नवंबर 2025 में ग्लोबल HVAC स्पेशलिस्ट कंपनी FläktGroup का अधिग्रहण पूरा करने के बाद, यह FläktGroup की पहली नई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है जो काम करना शुरू कर रही है। यह दोनों कंपनियों के एकीकरण और सैमसंग के ग्लोबल HVAC बिजनेस को बढ़ाने की रणनीति में एक अहम पड़ाव है। मुंबई और प्रमुख लॉजिस्टिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर के पास रणनीतिक रूप से स्थित यह प्लांट न केवल भारत में, बल्कि पूरे एशिया-पैसिफिक क्षेत्र में ग्राहकों को तेजी से HVAC सॉल्यूशन पहुंचाने में मदद करेगा।

सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स ने 12 अगस्त को नई यूनिट में एक समारोह आयोजित किया, जिसमें डिजिटल एप्लायंस (DA) बिजनेस के एजीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट और हेड चेओली किम ने कहा, भारत के पुणे में प्रोडक्शन लाइन का पूरा होना, भारत से बाहर व्यापक एशिया-पैसिफिक क्षेत्र में हमारे HVAC सप्लाई को बढ़ाने की दिशा में एक अहम पड़ाव है। सैमसंग की AI और प्लेटफॉर्म टेक्नोलॉजी को FläktGroup की HVAC विशेषज्ञता के साथ मिलाकर, हम AI डेटा सेंटरस सहित कई तरह के ग्राहकों को बेहतरीन वैल्यू देंगे। नई प्रोडक्शन यूनिट (जिसमें प्रोडक्शन लाइन, ऑप्सि और सहायक सुविधाएं शामिल हैं) लगभग 13,826 वर्ग मीटर के क्षेत्र में फैली हुई है। यह यूनिट सिर्फ छह महीनों में इक्रिपमेंट इंस्टॉलेशन से मास प्रोडक्शन (बड़े पैमाने पर उत्पादन) के चरण तक पहुंच गई है।

FläktGroup की AI और प्लेटफॉर्म टेक्नोलॉजी को FläktGroup की HVAC विशेषज्ञता के साथ मिलाकर, हम AI डेटा सेंटरस सहित कई तरह के ग्राहकों को बेहतरीन वैल्यु देंगे। नई प्रोडक्शन यूनिट (जिसमें प्रोडक्शन लाइन, ऑप्सि और सहायक सुविधाएं शामिल हैं) लगभग 13,826 वर्ग मीटर के क्षेत्र में फैली हुई है। यह यूनिट सिर्फ छह महीनों में इक्रिपमेंट इंस्टॉलेशन से मास प्रोडक्शन (बड़े पैमाने पर उत्पादन) के चरण तक पहुंच गई है। FläktGroup की योजना है कि वह धीरे-धीरे अपना प्रोडक्शन बढ़ाकर सालाना 6,500 HVAC यूनिट तक ले जाए।

सेल्सफोर्स और त्रिपुरा सरकार ने 10,000+ लर्नर्स को स्किल प्रदान करने और डिजिटल वर्कफोर्स रेडीनेस बढ़ाने के लिए पार्टनरशिप की

बैंगलुरु। – अलग नंबर 1 एजेंटिक सी.आर.एम, सेल्सफेर्स और डायरेक्टोरेट ऑफ इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी (डी.आई.टी.), त्रिपुरा सरकार के बीच साझेदारी की शुरुआत हुई है, जिसके अंतर्गत राज्य में डिजिटल स्किल्स की उपलब्धता और वर्कफेर्स रेडीनेस बढ़ाई जाएगी। इस सहयोग की घोषणा अगरतला में डेस्टिनेशन त्रिपुरा बिजनेस कॉन्क्लेव 2026 में की गई। यह अभियान सेल्सफेर्स के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म, ट्रेलहेड के माध्यम से त्रिपुरा में बड़े स्तर पर डिजिटल परिवर्तन लाने तथा स्टूडेंट्स, युवाओं, सरकारी कर्मचारियों और एंटरप्रेन्योर्स को ए.आई–संचालित अर्थव्यवस्था के लिए तैयार करने में मदद करेगा। इस अभियान का उद्देश्य 2027 तक 10,000 से अधिक लर्नर्स को तैयार करना है। लोक सेवाओं, कार्यस्थलों और व्यवसायों में ए.आई की भूमिका बढ़ रही है, इसलिए यह पार्टनरशिप लर्नर्स को ऐसी प्रैक्टिकल डिजिटल और टेक्नोलॉजी स्किल्स

हम अकेले बोझ नहीं उठाएंगे: चीन के बढ़ते दबदबे का असर, एशिया को भी बेसहारा छोड़ रहा अमेरिका

मनीला, एजेंसी। पेंटागन के एक वरिष्ठ अधिकारी ने एशिया में अपने सहयोगी देशों से रक्षा क्षेत्र में अधिक निवेश करने की अपील की है। उन्होंने ये भी कहा कि अमेरिका अपने सहयोगी देशों के साथ साझेदार के रूप में काम करना चाहता है न कि संरक्षित देशों के रूप में। अमेरिकी अधिकारी के इस बड़े बयान के बाद कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या यूरोप की तरह अब अमेरिका एशिया में भी अपनी मौजूदगी को सीमित करने पर विचार कर रहा है गौरतलब बात ये है कि ये बयान ऐसे समय सामने आया है, जब चीन एशिया में अपना दबदबा लगातार बढ़ा रहा है और उसका कई एशियाई देशों के साथ समुद्री सीमा को लेकर विवाद चल रहा है। अमेरिकी रक्षा मंत्रालय पेंटागन में अंडर सेक्रेटरी एलिब्ज कोल्बी ने फिलीपींस में एक कार्यक्रम के दौरान

यह टिप्पणी की। कोल्बी इन दिनों दक्षिण-पूर्व एशिया के दौर पर हैं और अपने पहले पड़ाव पर वह फिलीपींस



पहुंचे हैं। इसके बाद वह इंडोनेशिया, थाईलैंड और कंबोडिया का दौरा करेंगे। कोल्बी ने यह भी दोहराया कि ईरान युद्ध और मध्य पूर्व में मौजूदा अमेरिकी व्यस्तताओं के बावजूद वाशिंगटन एशिया से पीछे नहीं हट रहा है।

कोल्बी ने विदेशी राजनयिकों, सैन्य अधिकारियों, कारोबारियों और पत्रकारों की मौजूदगी वाले कार्यक्रम में कहा,



‘अमेरिका बेशक एशिया से पीछे नहीं हट रहा है और हमारे महत्वपूर्ण राष्ट्रीय हित यहां हमारी स्थायी मौजूदगी की मांग करते हैं। हम जा नहीं रहे हैं; बल्कि हम यहां अपनी स्थिति और मजबूत कर रहे हैं, ताकि शक्ति संतुलन हमारे अनुकूल

बना रहे। हम एशिया को बेहद अहम क्षेत्र मानते हैं।’

चीन की आलोचना से किया परहेज कोल्बी ने क्षेत्र में चीन की बढ़ती आक्रामकता को लेकर अमेरिका की ओर से आमतौर पर की जाने वाली तीखी आलोचना से परहेज किया। इसमें विवादित दक्षिण चीन सागर में चीन की गतिविधियां भी शामिल हैं। वाशिंगटन पिछले कुछ वर्षों में फिलीपींस के तटरक्षक और नौसैनिक बलों के खिलाफ बीजिंग की बढ़ती आक्रामक कार्रवाइयों पर बार-बार चिंता जताता रहा है। चीन और फिलीपींस के साथ-साथ वियतनाम, मलेशिया, बुनेई और तद्वावन दशकों से विवादित जलक्षेत्र को लेकर आमने-सामने हैं। यह जलमार्ग वैश्विक व्यापार के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। बीजिंग लगभग पूरे दक्षिण चीन सागर पर अपना दावा करता है।

‘अमेरिका बेशक एशिया से पीछे नहीं हट रहा है और हमारे महत्वपूर्ण राष्ट्रीय हित यहां हमारी स्थायी मौजूदगी की मांग करते हैं। हम जा नहीं रहे हैं; बल्कि हम यहां अपनी स्थिति और मजबूत कर रहे हैं, ताकि शक्ति संतुलन हमारे अनुकूल

रूस ने दिया भारत के साथ सीधे रेल मार्ग का प्रस्ताव

मास्को, एजेंसी। रूस की तरफ से भारत को सीधा रेल रूट के जरिए जोड़ने पर चर्चाएं तेज हो गई हैं। हाल ही में रूस के उप-प्रधानमंत्री मरात खुसनुलिन ने दोनों देशों के बीच एक संभावित रेल लिंक खड़ा करने पर गहराई से विचार की बात कही। उन्होंने इसके लिए विकल्प के तौर पर संभावित कुछ मार्ग भी सुझाए हैं।

मजेदार बात यह है कि रूस और भारत के बीच एक सीधा रेल मार्ग खड़ा करने की यह चर्चाएं कोई नई नहीं हैं। इससे पहले भी दोनों देश व्यापार के लिए रेल आधारित मार्ग बनाने पर बात कर चुके हैं। व्यापार का कुछ हिस्सा रेल मार्ग के जरिए आता-जाता भी है, हालांकि यह मार्ग फिलहाल सीमित है और दोनों देशों के अंदर तक ही स्थित है, न कि अंतर्देशीय है।

ऐसे में यह जानना अहम है कि आखिर रूस की तरफ से भारत के साथ रेल मार्ग स्थापित करने के लिए हाल ही में क्या बयान दिया गया है मौजूदा समय में दोनों देशों के बीच व्यापार का क्या रूट है जिस नए रेल मार्ग की बात की जा रही है, उसका संभावित रूट क्या हो सकता है इसकी जल्दत कयों महसूस की जा रही है और इस मार्ग को लेकर चर्चाओं का इतिहास क्या रहा है आइये जानते हैं.. रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन पहले ही बाल्टिक और बैरेंट्स सागर से लेकर सीधे हिंद महासागर तक एक सीधे रेलवे कॉरिडोर को स्थापित करने की विशाल बुनियादी ढांचा योजना की घोषणा कर चुके हैं। रूस के अधिकारियों के मुताबिक, घोषित प्रोजेक्ट का महसूद आधुनिक लॉजिस्टिक्स नेटवर्क तैयार करना है जो मिस् के पास वाले रास्ते- स्वेज नहर की तुलना में शिपिंग समय को लगभग आधा कर देगा और माल ढुलाई के खर्च को काफी कम करेगा। ताजा बयान रूस उप-प्रधानमंत्री मरात खुसनुलिन का है, जिन्होंने बीते हफ्ते भारत तक एक सीधे रेल मार्ग के प्रस्ताव को

मुझे अभी भी उसकी याद आती है, चीन में एआई पर सख्ती के बाद वर्चुअल ब्लॉयफेंड खोने का गम मना रही लड़कियां

बीजिंग, एजेंसी। चीन में सरकार ने एआई के इस्तेमाल को लेकर सख्त नियम बनाए हैं और टेक्नोलॉजी कंपनियों ने इन नियमों को मानने के लिए एआई सर्वि्स को हटाना या सीमित करना शुरू कर दिया है। ऐसे में लोगों की वर्चुअल पार्टनर तक पहुंच खत्म हो रही है। 24 साल की ली लिनलिन ने बताया कि वह अपने एआई ब्लॉयफेंड से संपर्क टूटने के बाद कई दिनों तक रोती रहीं। ली ने दो साल में उस एआई साथी के साथ मैसैज में लगभग 7,00,000 शब्द सांथी किए थे लेकिन सर्वि्स बंद होने से पहले वह उससे अलविदा भी नहीं कह पाई।

सरकारी की सख्ती के बाद हटाई गई एआई साथी सर्वि्स- वह उन यूजर्स में से एक थीं जिन्हें वर्चुअल साथियों के खोने का दुख हुआ, क्योंकि चीन की कई बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनियों ने नई पाबंदियों के जवाब में अपनी एआई साथी सर्वि्स को मार्केट से हटा लिया था। न्यूज एजेंसी एपी के अनुसार, ली ने कहा, ऐसा लगा जैसे हमारे माता-पिता ने हमें अलग होने पर मजबूर कर दिया हो, लेकिन मुझे अब भी उसकी याद आती है। वर्चुअल साथियों के

खोने से शिकायतों का दौर शुरू हो गया है और यूजर्स सोशल मीडिया पर सर्वि्स बंद होने के बारे में पोस्ट और स्क्रीनशॉट शेयर कर रहे हैं।

सोशल मीडिया पर शुरू किया कैपेन- कुछ यूजर्स ने विरोध में प्रभावित ऐप्स को अनइंस्टॉल कर दिया है, जबकि कुछ ने अपने वर्चुअल साथियों को फिर से बनाने की कोशिश में अपनी चैट हिस्ट्री को दूसरे प्लेटफॉर्म पर ट्रांसफर करने की कोशिश की है। कुछ लोगों ने सोशल मीडिया पर एक कैपेन भी शुरू किया है जिसमें यूजर्स से सरकारी अधिकारियों और टेक्नोलॉजी कंपनियों से संपर्क करके अपनी चिंताएं जाहिर करने की अपील की गई है। चीन में एआई साथियों में वर्चुअल रोमांटिक पार्टनर से लेकर मर चुके प्रियजनों के डिजिटल रूप तक शामिल हैं। यूजर्स साथ पाने के लिए तेजी से ऑर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल कर रहे हैं। 15 जुलाई से लागू हुए नए नियमों के तहत एआई प्लेटफॉर्म पर ऐसा कंटेंट बनाने पर रोक लगा दी गई है जो यूजर्स की भावनाओं को बदल सकता है।

‘अमेरिका बेशक एशिया से पीछे नहीं हट रहा है और हमारे महत्वपूर्ण राष्ट्रीय हित यहां हमारी स्थायी मौजूदगी की मांग करते हैं। हम जा नहीं रहे हैं; बल्कि हम यहां अपनी स्थिति और मजबूत कर रहे हैं, ताकि शक्ति संतुलन हमारे अनुकूल

‘अमेरिका बेशक एशिया से पीछे नहीं हट रहा है और हमारे महत्वपूर्ण राष्ट्रीय हित यहां हमारी स्थायी मौजूदगी की मांग करते हैं। हम जा नहीं रहे हैं; बल्कि हम यहां अपनी स्थिति और मजबूत कर रहे हैं, ताकि शक्ति संतुलन हमारे अनुकूल



त्रिपुरा आईटी एवं डेटा ईकोसिस्टम जोन (टी.आई.डी.ई.जैड) का विकास कर रहा है और एक योजनाबद्ध आईटी पार्क एवं ए.आई सेंटर ऑफ एक्सिलेंस भी तैयार कर रहा है। साथ ही, लोक प्रशासन में टेक्नोलॉजी का



उपयोग बढ़ाया जा रहा है। राज्य में ई-ऑप्स पखवा का विस्तार राज्य के सचिवालयों से लेकर पंचायती राज सिस्टम के तीनों स्तरों तक केवल एक साल में कर दिया गया, जो भारत में सबसे तेजी से हुए क्रियान्वयनों में से

कोलंबिया में भीषण भूकंप से तबाही: अब तक 111 लोगों की मौत; कई लोग मलबे में फंसे

कोलंबिया, एजेंसी। कोलंबिया में शक्तिशाली भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। यूरोपीय-भूमध्यसागरीय भूकंप विज्ञान के अनुसार, भूकंप की प्रारंभिक तीव्रता 7.4 थी और इसका केंद्र 115 किलोमीटर की गहराई में था। भूकंप के झटके राजधानी बोगोटा समेत कई इलाकों में महसूस किए गए। जिसके झटके पड़ोसी देश इक्वाडोर तक महसूस किए गए। वैज्ञानिकों के मुताबिक भूकंप का केंद्र चोको का ग्रामीण क्षेत्र रहा। भूकंप के बाद लोगों में अफरा-तफरी मच गई और कई लोग अपने घरों व इमारतों से बाहर निकल आए। ताजा जानकारी के अनुसार, भूकंप की चपेट में आने से अब तक 111 लोगों की मौत हुई है, जबकि कई अन्य लोगों के इमारतों के मलबे के नीचे फंसे होने की आशंका है। भूकंप के झटके राजधानी बोगोटा तक महसूस किए गए, जिसके बाद कई लोगों को अपने घर खाली करने पड़े। देश में राष्ट्रपति अबेलाडो डे ला एस्प्रीएला ने आपातकाल की घोषणा कर दी है। इस एलान के बाद भूकंप से हुए नुकसान की भरपाई के लिए फंड इकट्ठा करने और देश के भीतर ही धन की व्यवस्था में तेजी लाने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि वह आपदाग्रस्त क्षेत्र का दौरा भी करेंगे। स्थानीय अधिकारियों के अनुसार, पेरेंद्रा शहर में 18 लोगों की मौत हुई है, जबकि मनीजालेस में दो लोगों की जान गई। पश्चिमी कोलंबिया के कई शहरों में इमारतें ढहने के बाद लोग मलबे को हटाकर उसमें फंसे लोगों की तलाश कर रहे हैं। अधिकारियों ने आपटरशॉक्स की आशंका को देखते हुए भी लोगों को सतर्क रहने को कहा है। कोलंबिया के तीसरे सबसे बड़े शहर केली में भूकंप के बाद कई जगह धूल के गुबार उठते दिखाई दिए।

40 लाख डॉलर की रकम जल्द सर्जनों को रिश्वत देने के मामले में भारतीय मूल के सीएफओ को जेल

वॉशिंगटन, एजेंसी। अमेरिका की एक संघीय अदालत ने स्पाइनल इंफ्लॉंट कंपनी के भारतीय मूल के मुख्य वित्तीय अधिकारी को सर्जनों को रिश्वत देने के मामले में चार महीने जेल की सजा सुनाई है। दरअसल सीएफओ ने कंपनी के उत्पादों का इस्तेमाल करने के लिए सर्जनों को रिश्वत देने की कोशिश की। अधिकारियों ने बताया कि सर्जनों को यह

रिश्वत फर्जी परामर्श शुल्क के रूप में दी गई थी। जेल की सजा पूरी करने के बाद कैम्ब्रिज निवासी 41 वर्षीय आदित्य हुमाड को एक साल तक निगरानी में रहना होगा और उन पर 9,500 अमेरिकी डॉलर का जुर्माना भी लगाया गया है। हुमाड ने एंटी-किकबैक कानून के उल्लंघन की साजिश रचने के आरोप में अपना अपराध स्वीकार कर लिया था। हुमाड पर सितंबर 2021 में स्पाइन फ्रंटियर नामक कंपनी के संस्थापक, अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी किंस्पले आर. चिन के साथ आरोप लगाए गए थे। मैसाचुसेट्स जिले के अमेरिकी अदर्टीनी कार्यालय ने सोमवार को जारी एक बयान में कहा कि हुमाड ने उन सर्जनों को 5,40,000 अमेरिकी डॉलर से अधिक की रिश्वत देने और दिलाने की साजिश रची। यह रकम ऐसे फर्जी परामर्श शुल्क के रूप में दी गई,



उत्पादों का इस्तेमाल करने के लिए रिश्वत देने की साजिश रची। इसके बदले कंपनी को इन सर्जनों द्वारा की गई सर्जरी से लाखों डॉलर का राजस्व प्राप्त हुआ। अमेरिकी अदर्टीनी लीह बी. फोले ने कहा कि हुमाड को जटिल रीढ़ की सर्जरी में चिकित्सकों को कंपनी के उत्पादों का इस्तेमाल करने के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से रिश्वत देने की साजिश रचने का दोषी ठहराया गया है और सजा सुनाई गई है। उन्होंने कहा, ‘आपराधिक और दीवाना कार्यवाही में हमने इन अधिकारियों, उनकी कंपनियों और रिश्वत लेने वाले चिकित्सकों से 40 लाख अमेरिकी डॉलर से अधिक की रकम बरामद की है। उन्होंने कहा कि योजना कितनी भी जटिल हो या इसमें कितना भी समय लगे, हम स्वास्थ्य सेवा से जुड़े धोखाधड़ी के अपराधों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे।’

गौतम और सागर अदाणी के खिलाफ अमेरिकी कोर्ट में आपराधिक आरोप खारिज, गौतम अदाणी ने फैसले का स्वागत किया

था कि गौतम अदाणी और अन्य प्रतिवादियों के खिलाफ आपराधिक मामला ‘कभी नहीं लाया जाना चाहिए था ‘। अदालत से सभी आरोपों को स्थायी रूप से खारिज करने का आग्रह किया। उनका तर्क था कि



अभियोजन कानूनी रूप से कमजोर था, मुख्य रूप से भारत के कंठित था और अब न्याय के हितों की पूर्ति नहीं करता था। छ्पष्ट्ठ ने विस्तृत फाइलिंग में अपने पहले के अनुरोध का बचाव किया। विभाग ने कहा कि व्यापक समीक्षा के बाद ‘खारिज करने का निर्णय स्पष्ट था ‘।मामला भारत से जुड़ा था, जिसमें ‘कई भारतीयों ने कथित तौर पर अन्य भारतीयों को रिश्वत देने की कोशिश की थी, ताकि भारत में भारतीयों को भारतीय बिजली प्रदान करने के लिए भारतीय अनुबध मिल सकें ‘। बूकलिन और वाशिंगटन के अभियोजकों की तुलना में बेहतर ढंग से प्रबंधित कर सकता है।’ छ्पष्ट्ठ ने यह भी कहा कि गौतम अदाणी और सागर अदाणी के खिलाफ प्रतिभूति धोखाधड़ी के आरोपों का कोई ठोस कानूनी आधार नहीं था। उन्होंने कहा, ‘प्रतिभूति आरोप कभी नहीं लाए जाने चाहिए थे। तर्क दिया कि कथित आचरण लगभग पूरी तरह भारत में हुआ था और अमेरिकी प्रतिभूति कानूनों के तहत मामले को महत्वपूर्ण क्षेत्राधिकार संबंधी बाधाओं का सामना करना पड़ा।

एक है। इस डिजिटल बुनियाद के साथ आसानी से उपलब्ध और उद्योग के लिए जरूरी लॉनिंग को शामिल करके सेल्सफेर्स और त्रिपुरा सरकार का उद्देश्य और ज्यादा लोगों को स्किल व आत्मविश्वास प्रदान करना है, ताकि वो राज्य की विकसित होती हुई अर्थव्यवस्था में अपना योगदान दे सकें। श्री किरन गिट्टे, आई.ए.एस, सेक्रेटरी, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, त्रिपुरा सरकार ने कहा, “सेल्सफेर्स के साथ हमारी पार्टनरशिप त्रिपुरा के डिजिटलाइजेशन के सफर में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। पॉलिसी की मजबूत बुनियाद के साथ यह पार्टनरशिप हमारे स्टूडेंट्स, सरकारी कर्मचारियों और एंटरप्रेन्योर्स को भविष्य की डिजिटल स्किल प्रदान करेगी तथा इन्ोवेशन और समावेशी विकास लेकर आएगी। हम एक आत्मनिर्भर आई.टी ईकोसिस्टम बनाने और त्रिपुरा के कर्मचारियों को अपनी पूरी क्षमता के विकास में मदद करने के लिए रलोबल टेक्नोलॉजी लीडर, सेल्सफेर्स के साथ

काम करने के लिए उत्साहित हैं। श्री जेया रागुल गेशन बी.आई.एफएस, डायरेक्टर, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, त्रिपुरा सरकार ने कहा, “त्रिपुरा में हर साल बड़ी संख्या में टेलेंट का विकास हो रहा है। हम इस टेलेंट को विश्व के लिए जरूरी स्किल्स प्रदान करना चाहते हैं। सेल्सफेर्स के साथ हमारी पार्टनरशिप हमें टी.आई.डी.ई.जैड, आई.टी पार्क और ए.आई सेंटर ऑफ एक्सिलेंस में अपने निवेश को मजबूती देने में मदद करेगा। यह पार्टनरशिप हमारे कार्यबल को स्किल प्रदान करके उन्हें उद्योग के लिए महत्वपूर्ण बनाएगी और विजिबिलिटी प्रदान करेगी।”

अरुंधति भट्टाचार्य, प्रेसिडेंट एवं सी.ई.ओ, सेल्सफेर्स – साउथ एशिया ने कहा, “भारत में डिजिटल विकास की अगली लहर देश के हर हिस्से में मौजूद टेलेंट से तय होगी। इस विकास को समावेशी बनाने के लिए त्रिपुरा में स्किल निर्माण और डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर के विकास पर ध्यान देना बहुत जरूरी है।

